

सीजे सिन्हा ने कहा-जन विश्वास को बनाए रखना न्यायपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए

न्यायिक अकादमी में नव पदोन्नत जिला न्यायाधीशों का ओरिएंटेशन कोर्स शुरू

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में सोमवार को नव पदोन्नत जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कोर्स (अंतिम चरण) की शुरुआत हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सीजे ने कहा कि न्यायिक सेवा केवल अधिकार का नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का पद है। एक जिला न्यायाधीश की भूमिका न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों से परे नैतिक नेतृत्व की अपेक्षा भी रखती है, जिसमें विवेक, धैर्य और करुणा आवश्यक हैं। न्यायिक अध्ययन जीवन पर्यन्त चलता है, और विनम्रता उसकी सहचर होती है। यह ओरिएंटेशन कोर्स न केवल विधिक ज्ञान का विस्तार करेगा, बल्कि आपको आपके कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक तथा दृढ़ संकल्पित बनाएगा। सीजे ने निरंतर न्यायिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायिक दृष्टिकोण को परिष्कृत करने, मूल्यों को सुदृढ़ करने और जटिल कानूनी चुनौतियों से निपटने की क्षमता को विकसित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने न्यायाधीशों को निष्पक्ष, सहानुभूति और समयबद्ध निर्णय देने की सलाह दी। जन विश्वास को बनाए रखना न्यायपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तकनीकी नवाचारों की ओर संकेत करते हुए



28 जून तक चलेगा ओरिएंटेशन कोर्स

ओरिएंटेशन कोर्स 23 जून से 28 जून 2025 तक आयोजित होगा। यह वर्ष 2024 में नव पदोन्नत जिला न्यायाधीशों की नेतृत्व क्षमता और न्यायिक दक्षता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में तेजी से हो रहे परिवर्तन जैसे ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल अभिलेखों और एआई उपकरणों का उपयोग न्याय की पहुंच को व्यापक और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के सशक्त माध्यम बन रहे हैं। भविष्य के न्यायाधीशों को इन नवाचारों को आत्मसात कर कार्य प्रणाली में उत्कृष्टता लानी होगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी की अध्यक्ष जस्टिस रजनी दुबे, रजिस्ट्रार जनरल, अकादमी के अधिकारी और अन्य मौजूद रहे।